भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/332

विवि.एसटीआर.आरईसी.251/21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषयवस्तु

अध्याय I - प्रारंभिक 5

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – 5

बी. प्रयोज्यता 5

सी. परिभाषाएं 6

अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ 12

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां: 12

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग 15

सी. प्रकटीकरण 17

डी. पर्यवेक्षी समीक्षा 17

अध्याय III - समाधान प्रक्रिया 18

ए. समीक्षा अवधि 18

बी. अंतर- लेनदार समझौता 18

सी. समाधान योजना 19

अध्याय IV- अतिरिक्त प्रावधान 26

ए. समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब - अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानीकरण 26

अध्याय V – पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड 28

ए. प्रयोज्यता 28

बी. पुनर्रचना के बाद आस्ति का वर्गीकरण 28

सी. अतिरिक्त वित्त 28

डी. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आस्ति वर्गीकरण का उन्नयन 29

ई. निगरानी अवधि के बाद उधारकर्ता द्वारा चूक 30

एफ. पुनर्रचना के बाद प्रावधान 31

जी. आय निर्धारण 33

एच. स्वामित्व परिवर्तन 34

अध्याय VI - पुनर्रचना के विशेष मामले 36

ए. बिक्री और लीजबैक लेनदेन 36

बी. विदेशी मुद्रा उधार 36

सी. धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक करने वाले उधारकर्ता 37

डी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना 38

ई. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं 44

अध्याय VII - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) 54

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन: 54

अध्याय VIII: पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का विवेकपूर्ण उपचार 58

ए. पुनर्रचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का आस्ति वर्गीकरण 58

बी. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत लिखतों के संबंध में प्रावधान 58

सी. पुनर्रचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का मूल्यांकन 59

डी. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत उपकरणों से आय निर्धारण 62

अध्याय IX – वियामकीय छूट 63

ए. आरबीआई के विनियमों से छूट 63

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट 63

अध्याय X - विशेष उपाय 66

ए. व्यापार राहत उपाय 66

अध्याय XI - निरसन और अन्य प्रावधान 67

ए. निरसन और बचाव 67

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं 68

सी. व्याख्याएँ 68

अनुलग्नक 70

प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। चूंकि समझौता समझौते एक वैध समाधान योजना है, इसलिए ये निदेश प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए समझौता समझौतों और तकनीकी बट्टे-खाते डालना पर निर्देशों को तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण भी बनाते हैं। इसके अलावा, इन निर्देशों में बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचे (वाणिज्यिक अचल संपत्ति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति-आवासीय आवास सहित) में परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तारीख में परिवर्तन पर समेकित नियामक उपचार निर्धारित किया गया है।

कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समर्थन के बदले उधारकर्ताओं के लक्षित वर्ग के ऋण दायित्वों का त्याग / छूट शामिल है। यदि ऐसी योजनाओं की घोषणा बार-बार, असंगत रूप से, या वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की जाती है, तो इससे ऋण अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लंबे समय में, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के लिए प्रति-उत्पादक हो सकता है। क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे के मुद्दों के व्यापक निहितार्थों के अलावा, डीआरएस कुछ विवेकपूर्ण चिंताओं को भी बढ़ाता है, जिसमें बकाया राशि की प्राप्ति में देरी; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकार किए गए दावों और संबंधित सरकार द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा नए ऋण की अनिवार्य आवश्यकता आदि शामिल हैं। ये निदेश डीआरएस में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांतों को भी निर्धारित करते हैं और

एक मॉडल संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इन निर्देशों को जारी करता है जो इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इन निदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान– दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों' और व्यक्तिगत रूप से 'एआईएफआई' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे अर्थात भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएएफआईडी)।

सी. परिभाषाएं

4. इन निर्देशों में, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो:

(1) '*एग्रीगेट एक्सपोजर*' में निवेश एक्सपोजर सहित सभी निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे;

(2) *समझौता निपटान' का अर्थ* उधारकर्ता के विरुद्ध एआईएफआई के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा ।

स्पष्टीकरण: समझौता निपटान में उधारकर्ता के हिस्से पर एआईएफआई से देय राशि का कुछ त्याग शामिल हो सकता है, जिससे उधारकर्ता के खिलाफ एआईएफआई के दावों की उसी सीमा तक छूट हो सकती है।

(3) *कार्यान्वित परियो*जना के संदर्भ में 'क्रेडिट घटना' निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर शुरू की गई मानी जाएगी:

(i) किसी भी ऋणदाता के साथ चूक;

(ii) एक या अधिक ऋणदाता किसी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) की मूल / विस्तारित प्रारंभ तिथि के विस्तार की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, जैसा भी मामला हो;

(iii) मूल / विस्तारित डीसीसीओ की समाप्ति, जैसा भी मामला हो;

(iv) एक या अधिक ऋणदाता अतिरिक्त ऋण के लिए आवश्यकता निर्धारित करते हैं;

(v) परियोजना को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो पैरा 7 से 9 के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(4) '*चूक*' का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई है और देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(5) '*निर्माण के दौरान ब्याज' का अर्थ* एआईएफआई द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर अर्जित ब्याज और परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पूंजीकृत ब्याज होगा;

(6) प*रियोजना* वित्त के संदर्भ में 'ऋणदाता' का अर्थ निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई भी होगा:

(i) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान(लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को छोड़कर भुगतान बैंक (पीबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित);

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) सहित)

(iii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;

(iv) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान।

(7) '*परिसमापन मूल्य' का* अर्थ प्रासंगिक उधारकर्ता की संपत्तियों का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य होगा, यदि ऐसे उधारकर्ता को समीक्षा अवधि की शुरुआत की तारीख को परिसमाप्त किया जाना था;

(8) नि*गरानी अवधि का अर्थ* समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक की अवधि होगी, जब तक कि समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्रचना के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है;

(9) '*बकाया मूलधन ऋण' में सभी क्रे*डिट सुविधाएं शामिल होंगी, जिसमें ऋण / ऋण जैसे उपकरण (अर्थात, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर, गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर आदि) शामिल हैं जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद मौजूद हैं।

स्पष्टीकरण: केवल इक्विटी और इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय उपकरण (बिना किसी वैकल्पिक विकल्प के) को बकाया मूल ऋण निर्धारित करने से छूट दी जाएगी।

(10) अ*वशिष्ट ऋण का* अर्थ होगा प्रस्तावित समाधान योजना के अनुसार सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा रखे जाने वाले सभी बकाया मूल ऋण;

(11) *कार्यान्वित की जा*रही परियोजनाओं के संदर्भ में 'समाधान योजना' का अर्थ है परियोजना वित्त खाते में तनाव के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से सहमत, कानूनी रूप से बाध्यकारी, व्यवहार्य और समयबद्ध योजना। समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई /

योजना / पुनर्रचना शामिल हो सकता है, जिसमें देनदार इकाई द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान द्वारा खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं / निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन, डीसीसीओ का विस्तार और पुनर्रचना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(12) पुनर्रचना *का अर्थ* एक ऐसा कार्य होगा जिसमें एआईएफआई, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण: पुनर्रचना में आम तौर पर अग्रिम / प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा, जिसमें आम तौर पर अन्य बातों के अलावा, भुगतान अवधि / देय राशि / किश्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होगा; क्रेडिट सुविधाओं का रोल ओवर; अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा की मंजूरी / चूक के इलाज में सहायता के लिए चूक में खाते के लिए अतिरिक्त धन जारी करना / मौजूदा क्रेडिट सीमा में वृद्धि; समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक है।

(13) स*मीक्षा अवधि' का* अर्थ चूक या क्रेडिट घटना की तारीख से 30 दिनों की अवधि होगी, जैसा भी मामला हो;

(14) '*संतोषजनक प्रदर्शन' का अर्थ* होगा कि उधारकर्ता इकाई संबंधित अवधि के दौरान किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ चूक नहीं है;

(15) *निर्दिष्ट ऋणदाता'* का अर्थ निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई भी होगा:

(i) वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी सहित लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर);

(ii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान।

(iii) जमा लेने वाली एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर);

(iv) गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) जिसकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ और उससे अधिक है।

(16) *निर्दिष्ट अवधि का अर्थ* है समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि जब समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 20 प्रतिशत और **पुनर्रचना** के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है।

बशर्ते कि आईबीसी के तहत पुनर्गठित खातों के लिए, निर्दिष्ट अवधि को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से शुरू माना जाएगा।

(17) '*स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा' का अर्थ* है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान किसी भी लागत के अतिप्रवाह को निधि देने के लिए वित्तीय समापन के समय परियोजना के लिए स्वीकृत एक आकस्मिक क्रेडिट लाइन।

(18) *तकनीकी* बट्टे-खाते डालना*' उन मा*मलों को संदर्भित करेगा जहां गैर-निष्पादित *आस्ति*यां उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया रहती हैं, लेकिन किसी भी ऋण के खिलाफ दावों की छूट के बिना, और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, केवल लेखा उद्देश्यों के लिए एआईएफआई द्वारा *बट्टे-खाते डालना* (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) की जाती है।

5. 'नियुक्त तिथि'*, 'वाणिज्यिक अ*चल *संपत्ति (सीआरई), 'वाणिज्यिक* अचल *संपत्ति - आवास (सीआरई-आरएच), 'निर्माण चर*ण', *'वित्तीय समापन की* तारीख*', 'बुनियादी ढांचा क्षेत्र*, '*वाणिज्यिक परिचालन शुरू* होने *की मूल तिथि (मूल डीसीसीओ), 'विस्तारित डीसीसीओ', 'वास्तविक डीसीसीओ', 'परियोजना', और 'परि*योजना *वित्त' का क*ही अर्थ *होगा जो* भारतीय *रिजर्व बैंक (*अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- ऋण सुविधाएं) *निदेश*, 2025 में परिभाषित किया गया है।

6. अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि यहाँ परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ रखती हैं जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन या रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किए जाने वाले, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।

अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां:

7. एआईएफआई, वित्तीय कठिनाई के निर्धारण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक पैरामीटरों के साथ-साथ वित्तीय कठिनाई के विभिन्न संकेतों पर विस्तृत नीतियों के साथ-साथ समाधान के लिए समय-सीमा सहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा।

8. वित्तीय कठिनाई के संकेतों की गैर-विस्तृत सांकेतिक सूची, जो 'गैर-निष्पादित एक्सपोजरों और रियायत की परिभाषाओं पर समस्यामूलक आस्तियों के विवेकपूर्ण निष्पादन' पर बासल समिति के दिशानिर्देशों पर आधारित है, को संदर्भ के लिए निम्नानुसार प्रदान की गई है:

(1) फ्रेमवर्क में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार, चूक (*चूक*) को वित्तीय कठिनाई के लिए एक संकेतक के रूप में माना जाएगा, यद्यपि चूक के कारण कुछ भी हों।

(2) उधारकर्ता की चूक नहीं है, लेकिन यह संभव है कि उधारकर्ता निकट भविष्य में रियायत के बिना अपने किसी भी एक्सपोजर में चूक कर सकता है, उदाहरण के लिए, जब इसके एक्सपोजर पर भुगतान में अपराध का एक पैटर्न रहा है।

(3) ऋणकर्ता की बकाया प्रतिभूतियों को सूची से हटाया गया है या सूची से हटाने की प्रक्रिया में है, या सूची की शर्तों का पालन न करने या वित्तीय कारणों से किसी एक्सचेंज से सूची से बाहर होने का खतरा है।

(4) वास्तविक प्रदर्शन, अनुमानों और प्रोजेक्षण के आधार पर जो उधारकर्ता के परिचालनों के वर्तमान स्तर को सम्मिलित करते हैं, उधारकर्ता के नकदी प्रवाह का आकलन अनुबंधित शर्तों के अनुसार अपने सभी ऋण या ऋण प्रतिभूतियों (ब्याज और मूलधन दोनों) के क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त है।

(5) उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधाएं गैर-निष्पादित स्थिति में हैं या रियायतों के बिना गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

(6) उधारकर्ता के मौजूदा एक्सपोजर को उन एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उधारकर्ता की एआईएफआई की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार पुनर्भुगतान करने की क्षमता में पहले से ही कठिनाई का प्रमाण दे चुके हैं।

9. एआईएफआई, वित्तीय कठिनाई संकेतकों की उपरोक्त अपरिपूर्ण गणना के पूरक के रूप में प्रमुख वित्तीय अनुपातों और परिचालन मानदंडों के साथ-साथ मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को भी शामिल करेगा।

स्पष्टीकरण: एक्सपोजर पर बकाया राशि के अभाव में भी वित्तीय कठिनाई की पहचान की जा सकती है।

10. एआईएफआई, उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी बट्टे-खाते के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न*लिखित शामि*ल होंगे:

(1) सभी समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक निर्धारण, अपेक्षित शर्तों के विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जैसे न्यूनतम परिपक्वन, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि;

(2) बोर्ड द्वारा तय की जानेवाली उचित सीमा और समय-सीमा के साथ ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा;

(3) उपलब्धता के अनुसार, प्रतिभूति / संपार्श्विक के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की विवेकपूर्ण गणना के बाद निपटान राशि पर पहुंचने के दौरान विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोजर के लिए अनुमेय घाटा से संबंधित प्रावधान;

(4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य पर पहुंचने के लिए कार्यप्रणाली।

(5) निम्नलिखित के अधीन समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के अनुमोदन / मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन:

(i) इस तरह की मंजूरी के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन एक प्राधिकरण (व्यक्ति या समिति, जैसा भी मामला हो) के पास होता है जो क्रेडिट / निवेश एक्सपोजर को मंजूरी देने के लिए शक्ति निहित प्राधिकरण की तुलना में पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊंचा होता है।

बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो ऋण स्वीकृत करने का हिस्सा था (व्यक्तिगत या समिति के हिस्से के रूप में) किसी भी क्षमता में उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हिस्सा नहीं होगा।

(ii) धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में समझौते के प्रस्तावों के लिए, जैसा कि पैरा 83 से 98 के संदर्भ में अनुमत है, सभी मामलों में बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।

11. एआईएफआई, पैरा 42 और 43 के संदर्भ में आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त व्युत्पन्न अनुबंधों के क्रिस्टलीकृत बाजार भाव पर दर्शानेवाले (मार्क टू मार्केट) (एमटीएम) मूल्य को किस्त में भुगतान की अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा।

12. बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई नीति की सुदृढ़ता और परिणामों की जांच रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी निगरानी के हिस्से के रूप में की जाएगी।

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

13. एआईएफआई, ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की चूक की शीघ्र पहचान ऐसी आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके करेगा:

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णत: या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिन तक

एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

14. उधारकर्ता के खातों के एसएमए श्रेणियों में वर्गीकरण के निदेश विनियमित संस्थाओं के एक्सपोजर आकार पर विचार किए बिना फसल मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों के अलावा सभी ऋणों (खुदरा ऋणों सहित) के लिए लागू हैं।

15. एआईएफआई, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं की, मासिक आधार पर, खाते के एसएमए के रूप में वर्गीकरण सहित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को करेगा।

16. एआईएफआई, प्रत्येक शुक्रवार को कारोबार के समापन पर या पिछले कार्य दिवस पर यदि शुक्रवार को छुट्टी होती है तो सभी उधारकर्ताओं (₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर के साथ) द्वारा चूक के उदाहरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17. एआईएफआई को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2017 की सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और संहिता और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करेगा।

सी. प्रकटीकरण

18. एआईएफआई अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा के नोट्स' में उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- वित्तीय विवरण: प्रस्तुतियां और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट किया गया है।

डी. पर्यवेक्षी समीक्षा

19. खातों की वास्तविक स्थिति को छुपाने या दबावग्रस्त खातों को सतत बनाने के प्रयोजन से एआईएफआई द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले कठोर पर्यवेक्षी / प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन होगी, जिसमें ऐसे खातों पर उच्च प्रावधान और मौद्रिक दंड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अध्याय III - समाधान प्रक्रिया

ए. समीक्षा अवधि

20. एक बार जब किसी एनबीएफसी के अलावा किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता द्वारा किसी उधारकर्ता को चूक (चूक) होने की सूचना दी जाती है, तो निर्दिष्ट ऋणदाता संयुक्त रूप से समीक्षा अवधि के भीतर उधारकर्ता के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा करेंगे।

21. इस समीक्षा अवधि के दौरान, निर्दिष्ट ऋणदाता संयुक्त रूप से समाधान कार्यनीति पर निर्णय लेंगे, जिसमें समाधान योजना की प्रकृति, समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।

22. एआईएफआई, शोधन अक्षमता या वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का विकल्प भी चुन सकता है।

23. चूंकि किसी भी ऋणदाता के साथ चूक करना, उधारकर्ता को होनेवाले वित्तीय तनाव का एक पिछड़ने वाला संकेतक है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि एआईएफआई चूक से पहले ही समाधान योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें।

बी. अंतर- लेनदार समझौता

24. ऐसे मामलों में जहां समाधान योजना को लागू किया जाना है, सभी निर्दिष्ट ऋणदाता, एक से अधिक निर्दिष्ट ऋणदाता से ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को अंतिम

रूप देने और कार्यान्वयन के लिए मूल नियमों के प्रावधान के लिए, समीक्षा अवधि के दौरान, एक अंतर-ऋणदाता समझौता करेंगे।

25. अंतर-लेनदार समझौते में यह प्रावधान किया जाएगा कि:

(1) कोई भी निर्णय जिस पर कुल बकाया क्रेडिट सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के 75 प्रतिशत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्ताक्षरकर्ता और संख्या के हिसाब से 60 प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ता सहमत होते हैं, वह सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा; और

(2) समाधान योजनाओं में असहमति जताने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं को देय परिसमापन मूल्य से कम भुगतान का प्रावधान किया जाएगा।

26. उपरोक्त पैरा 25 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अलावा, अंतर-लेनदार करार में, अन्य बातों के अलावा, *बहुमत हस्ता*क्षरकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों, असहमत हस्ताक्षरकर्ताओं के कर्तव्यों और अधिकारों की सुरक्षा, नकदी प्रवाह / विभेदक सुरक्षा ब्याज आदि में प्राथमिकता के साथ हस्ताक्षरकर्ताओं के निष्पादन के लिए प्रावधान किया जाएगा।

सी. समाधान योजना

27. समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई / योजना / पुनर्रचना शामिल हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता संस्था द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान द्वारा खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं / निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन और पुनर्रचना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

28. एआईएफआई द्वारा समाधान योजना को स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा (भले ही किसी भी नियम और शर्तों में कोई बदलाव न हो)।

29. जिन खातों में निर्दिष्ट ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, उनमें पुनर्रचना / स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित समाधान योजना के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से अवशिष्ट ऋण का स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन आवश्यक होगा।

30. आरपी प्रतीकों की सूची जो स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन के रूप में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाएगी और उनके अर्थ निम्नानुसार हैं:

आईसीई **प्रतीक**	**परिभाषा**
1	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा मानते हैं। इस तरह की ऋण सुविधाएं / उपकरण सबसे कम क्रेडिट एक्सपोजर रखते हैं।
2	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा मानते हैं। इस तरह की ऋण सुविधाएं / उपकरण बहुत कम क्रेडिट एक्सपोजर रखते हैं।
आरपी3	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा की डिग्री मानते हैं। इस तरह की ऋण सुविधाएं / उपकरण कम क्रेडिट एक्सपोजर रखते हैं।

आरपी4	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में सुरक्षा की मध्यम डिग्री मानते हैं। इस तरह की ऋण सुविधाएं / उपकरण मध्यम क्रेडिट एक्सपोजर रखते हैं।
आरपी5	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में चूक के मध्यम एक्सपोजर वाले माने जाते हैं।
आरपी6	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में चूक के उच्च एक्सपोजर वाले माने जाते हैं।
आरपी 7	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाएं / उपकरण वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में चूक के बहुत उच्च एक्सपोजर वाले माने जाते हैं।

31. जबकि ₹500 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों के लिए दो स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, अन्य के लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

32. केवल ऐसी समाधान योजनाएं जिन्हें एक या दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अवशिष्ट ऋण के लिए आरपी4 या बेहतर की क्रेडिट राय प्राप्त होती है, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

33. यदि आवश्यक संख्या से अधिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है, तो कार्यान्वयन के लिए विचार किए जाने वाले समाधान योजना के लिए सभी स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन राय आरपी4 या इससे बेहतर होगी।

34. स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा सीधे नियुक्त किया जाएगा और ऐसे असाइनमेंट के लिए शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा किया जाएगा।

35. जिस अवधि के दौरान आरपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है, उस दौरान इस निदेश के अध्याय IV के अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अधीन सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होते रहेंगे। किसी आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि आरपी विचाराधीन है।

36. जिन उधारकर्ताओं के संबंध में एक या अधिक निर्दिष्ट ऋणदाताओं का क्रेडिट एक्सपोजर जारी है, उनके संबंध में समाधान योजना को केवल तभी 'कार्यान्वित' माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों जाएगी:

(1) समाधान योजना जिसमें पुनर्रचना / स्वामित्व में परिवर्तन शामिल नहीं है, केवल तभी लागू मानी जाएगी जब उधारकर्ता समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180वें दिन तक निर्दिष्ट उधारदाताओं में से किसी के साथ चूक नहीं है। 180-दिवसीय अवधि के बाद कोई कोई भी चूक, एक नई चूक मानी जाएगी, जो एक नई समीक्षा को उत्प्रेरित (ट्रिगर) करेगी।

(2) समाधान योजना जिसमें पुनर्रचना / स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है, केवल तभी लागू माना जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(i) निर्दिष्ट उधारदाताओं और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन / प्रतिभूति प्रभार / प्रतिभूतियों की पूर्णता सहित सभी संबंधित दस्तावेज़, कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप संबंधित निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा पूरा किया जाता है;

(ii) नई पूंजी संरचना और / या मौजूदा ऋणों की शर्तों में परिवर्तन सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं और उधारकर्ता की पुस्तकों में विधिवत प्रतिबिंबित होते हैं; और,

(iii) उधारकर्ता निर्दिष्ट उधारदाताओं में से किसी के साथ चूक नहीं है।

37. एक समाधान योजना जिसमें निर्दिष्ट ऋणदाताओं को तीसरे पक्ष को असाइन करके एक्सपोजर से बाहर निकलने या वसूली कार्रवाई से जुड़ी एक समाधान योजना शामिल है, केवल तभी लागू माना जाएगा जब उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर पूरी तरह से समाप्त हो जाए।

38. निर्दिष्ट ऋणदाताओं के साथ निर्दिष्ट सीमा से अधिक कुल एक्सपोजर वाले खातों के संबंध में 'संदर्भ तिथि' पर या उसके बाद, समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर समाधान योजना लागू की जाएगी, जो बाद में शुरू नहीं होगी:

(1) संदर्भ तिथि, यदि संदर्भ तिथि पर *चूक* के रूप में

(2) संदर्भ तिथि के बाद पहले चूक की तारीख।

39. उपरोक्त पैरा 38 के प्रयोजन के लिए संदर्भ तिथियां निम्नानुसार होंगी:

एनबीएफसी के अलावा निर्दिष्ट ऋणदाताओं के लिए एक उधारकर्ता का कुल एक्सपोजर	**संदर्भित दिनांक**
2000 करोड़ रुपये और उससे अधिक	07 जून, 2019
1500 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 2000 करोड़ रुपये से कम	1 जनवरी 2020
1500 करोड़ रुपये से कम	नियत समय में घोषित किया जाना है

40. 1,500 करोड़ रुपये से कम के कुल एक्सपोजर वाले खातों के संबंध में, इन निर्देशों के अध्याय IV के तहत निर्धारित आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी।

41. जहां एक व्युत्पन्न अनुबंध का पुनर्रचना किया जाता है, निम्नलिखित निदेश लागू होंगे:

(1) मूल अनुबंध के किसी भी पैरामीटर में कोई भी बदलाव पुनर्रचना माना जाएगा।

(2) *पुनर्रचना* की तारीख को अनुबंध के मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य में परिवर्तन को नकद में सेटल किया जाना चाहिए।

(3) डेरिवेटिव अनुबंध का *पुनर्रचना* प्रचलित बाजार दरों पर किया जाएगा, न कि ऑफ-मार्केट दरों के आधार पर।

42. यदि कोई एआईएफआई, हेजिंग व्युत्पन्न अनुबंध के काल्पनिक एक्सपोजर को कम करने के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर, अपनी इच्छानुसार, परिपक्वता से पहले व्युत्पन्न अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, तो काल्पनिक एक्सपोजर में इस तरह की कमी को

व्युत्पन्न अनुबंध के पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि मूल अनुबंध के अन्य सभी पैरामीटर अपरिवर्तित रहें।

43. ऐसे मामलों में, यदि व्युत्पन्न अनुबंध का एमटीएम मूल्य नकद रूप से तय नहीं किया गया है, तो एआईएफआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन, ऐसे व्युत्पन्न अनुबंधों (विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों सहित) के क्रिस्टलीकृत एमटीएम के किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है:

(1) एआईएफआई, किश्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति तभी देगा जब ग्राहक द्वारा पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता हो।

(2) पुनर्भुगतान अवधि अनुबंध की परिपक्वता तिथि से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) क्रिस्टलीकृत एमटीएम के लिए पुनर्भुगतान किस्तें अनुबंध की शेष परिपक्वता पर समान रूप से प्राप्त की जाएंगी और इसकी समय-समय पर कम से कम एक तिमाही में एक बार होगी।

अध्याय IV- अतिरिक्त प्रावधान

ए. समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब - अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानीकरण

44. जहां 36 और 37 पैरा में निर्दिष्ट उधारकर्ता के संबंध में एक व्यवहार्य समाधान योजना नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर लागू नहीं की जाती है, तो उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर रखने वाला एआईएफआई निम्नलिखित के रूप में अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करेगा:

व्यवहार्य आरपी के कार्यान्वयन की समयरेखा	**कुल बकाया (निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित) के प्रतिशत के रूप में किए जाने वाले अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान, यदि आरपी समय सीमा के भीतर लागू नहीं किया गया है**
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20 प्रतिशत
समीक्षा अवधि की प्रारम्भ से 365 दिन	15 प्रतिशत (यानी कुल अतिरिक्त प्रावधान 35 प्रतिशत)

45. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान निम्नलिखित में से उच्चतर से और ऊपर किए जाएंगे, कुल बकाया राशि के 100 प्रतिशत पर सीमित कुल प्रावधानों के अधीन:

(1) पहले से ही किए गए प्रावधान; या,

(2) उधारकर्ता खाते के आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए जाने वाले प्रावधानों की आवश्यकता।

46. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान उन मामलों में भी किए जाने होंगे जहां उधारकर्ता के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, जब तक कि वसूली की कार्यवाही पूरी तरह से पूरी न हो जाए।

47. पैरा 44 में निर्दिष्ट अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को निम्नानुसार उलट दिया जा सकता है:

(1) जहां समाधान योजना में उधारकर्ता द्वारा केवल अतिदेय राशि का भुगतान शामिल है - अतिरिक्त प्रावधान केवल तभी उलट सकते हैं जब उधारकर्ता सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं के साथ अतिदेय राशि को समाशोधित करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए चूक नहीं है;

(2) जहां समाधान योजना में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से परे स्वामित्व में पुनर्रचना / परिवर्तन सम्मिलित है - समाधान योजना के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त प्रावधानों को उलट दिया जा सकता है;

(3) जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत समाधान का अनुसरण किया जाता है - किए गए अतिरिक्त प्रावधानों में से आधे को दिवाला आवेदन दाखिल करने पर उलट दिया जा सकता है और शेष अतिरिक्त प्रावधानों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया में उधारकर्ता के प्रवेश पर उलट दिया जा सकता है; या,

(4) जहां ऋण / वसूली कार्यवाही शुरू की जाती है - ऋण / वसूली के असाइनमेंट के पूरा होने पर अतिरिक्त प्रावधानों को उलट दिया जा सकता है।

अध्याय V – पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड

ए. प्रयोज्यता

48. इस अध्याय के प्रावधान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत की गई पुनर्रचना सहित सभी पुनर्रचनाओं पर लागू होंगे।

बी. पुनर्रचना के बाद आस्ति का वर्गीकरण

49. 'मानक' रूप में वर्गीकृत खाते को तत्काल गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में डाउनग्रेड किया जाएगा, अर्थात एआईएफआई द्वारा पुनर्रचना के बाद प्रारम्भ करने के लिए 'उप-मानक'।

50. गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत खाते को एआईएफआई द्वारा पुनर्रचना के बाद, पुनर्रचना से पहले समान आस्ति वर्गीकरण बनाए रखना होगा।

51. उपरोक्त दोनों मामलों में, आस्ति वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान-आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार परिपक्वन के मानदंडों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा।

सी. अतिरिक्त वित्त

52. समाधान योजना के तहत अनुमोदित कोई भी अतिरिक्त वित्त (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी समाधान योजना सहित) को एआईएफआई द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तहत निगरानी अवधि के दौरान मानक

संपत्ति के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि खाता निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करता है।

53. यदि पुनर्रचित आस्ति निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहती है या निगरानी अवधि के अंत में उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है, तो अतिरिक्त वित्त को एआईएफआई द्वारा पुनर्रचित ऋण के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा।

54. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत शोधन अक्षमता कार्यवाही से गुजर रहे उधारकर्ताओं को निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा विस्तारित कोई भी अंतरिम वित्त [दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 (15) में परिभाषित] को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में परिभाषित शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान मानक संपत्ति माना जा सकता है।

डी. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आस्ति वर्गीकरण का उन्नयन

55. किसी एआईएफआई द्वारा पुनर्रचना पर एक ही श्रेणी में बनाए रखे गए गैर-निष्पादित और गैर-निष्पादित खातों के रूप में वर्गीकृत मानक खातों को केवल तभी उन्नत किया जा सकता है जब खाते में सभी बकाया ऋण / क्रेडिट सुविधाएं निगरानी अवधि के दौरान सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं के संबंध में 'संतोषजनक प्रदर्शन' प्रदर्शित करती हैं।

बशर्ते कि आरपी की शर्तों के तहत सबसे लंबी अवधि की ऋणस्थगन क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान की शुरुआत से एक वर्ष से पहले खाते को उन्नत नहीं किया जा सकता है।

56. पैरा 55 की अपेक्षाओं के अलावा, उन खातों के लिए जहां समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय निर्दिष्ट उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ और उससे अधिक है, उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, संतोषजनक प्रदर्शन के प्रदर्शन के अलावा, उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधाओं को बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन्नयन के समय निवेश ग्रेड (बीबीबी- या बेहतर) के रूप में भी रेट किया जाएगा।

बशर्ते कि 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों के लिए दो रेटिंग की आवश्यकता होगी, जबकि 500 करोड़ रुपये से कम के खातों के लिए एक रेटिंग की आवश्यकता होगी।

बशर्ते कि यदि रेटिंग आवश्यक संख्या से अधिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त की जाती है, तो ऐसे सभी रेटिंग खाते के उन्नयन के लिए निवेश ग्रेड होंगे।

स्पष्टीकरण: दूसरे परंतुक में उल्लिखित ये रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सामान्य रेटिंग होंगी, न कि पैरा 29 में निर्दिष्ट स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन।

57. यदि संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करने में विफल रहता है, तो आस्ति वर्गीकरण उन्नयन इन निदेशों के तहत या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत एक नए पुनर्रचना / स्वामित्व में परिवर्तन के कार्यान्वयन के अधीन होगा।

ई. निगरानी अवधि के बाद उधारकर्ता द्वारा चूक

58. उधारकर्ता द्वारा किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ किसी भी ऋण सुविधा में किसी भी प्रकार की चूक, जो आस्ति वर्गीकरण में उन्नयन के बाद निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले होती है, के

लिए निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर एक नया समाधान योजना लागू करना आवश्यक होगा, क्योंकि किसी भी चूक का परिणाम इसके साथ जुड़ा होगा।

एफ. पुनर्रचना के बाद प्रावधान

59. पुनर्रचित किए गए खाते को भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार प्रावधान लागू होंगे।

60. एआईएफआई, समीक्षा अवधि के अंत में पैरा 57 और 58 में उल्लिखित खाते के लिए 15 प्रतिशत का अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करेगा।

61. उपरोक्त पैरा 59 के अनुसार एआईएफआई द्वारा पुनर्रचित आस्तियों पर धारित विशिष्ट प्रावधानों को तब उलट दिया जा सकता है जब खातों को मानक श्रेणी में उन्नत किया जाता है।

62. पैरा 60 के तहत आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त प्रावधानों को एआईएफआई द्वारा पैरा 47 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उलट दिया जा सकता है।

63. दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान, अंतरिम वित्त के लिए प्रावधान , भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 द्वारा शासित होंगे।

64. इसके बाद, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर, ऐसे अंतरिम वित्त का निष्पादन अतिरिक्त वित्त के लिए लागू मानदंडों के अनुसार होगा, जैसा कि पैरा 52 और 53 में दिया गया है।

65. उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में जहां ऋणदाता समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम समाधान योजना, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए समाधान प्रोफेशनल द्वारा प्रस्तुत की गई है (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 30(6) के संदर्भ में), एआईएफआई योजना प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 31 (1) के संदर्भ में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से 90 दिनों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्थगित रख सकता है।

बशर्ते, जिन मामलों में प्रावधान अपेक्षित आवश्यक प्रावधान से कम है, एआईएफआई कमी की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करेगा।

66. पैरा 65 के अनुसार प्रावधान की मात्रा को फ्रीज करने की सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने की तारीख तक एआईएफआई द्वारा रखे गए प्रावधान, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर सामान्य स्थितियों में किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान से अधिक हो, जिसमें मामले के अनुसार, ऋणदाताओं की समिति / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की रूपरेखा और मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

67. पैरा 66 के बावजूद, एआईएफआई को इस चरण में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख पर धारण किए गए अतिरिक्त प्रावधानों को उलटने का अधिकारी नहीं होगा।

68. पैरा 65 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 की अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

69. पैरा 65 में अनुमत प्रावधानों को फ्रीज करने की सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना को खारिज कर देता है, और ऐसे उधारकर्ता के संबंध में आस्ति वर्गीकरण मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित होना जारी रहेगा।

जी. आय निर्धारण

70. पुनर्रचित खातों के संबंध में ब्याज आय को 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और 'गैर-निष्पादित आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के संबंध में इसे नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

71. खातों में अतिरिक्त वित्त के मामले में जहां पुनर्रचना से पहले की सुविधाओं को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ब्याज आय को केवल एआईएफआई द्वारा नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी, जब पुनर्रचना स्वामित्व में परिवर्तन होता है।

एच. स्वामित्व परिवर्तन

72. उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में, संबंधित उधार लेने वाली संस्थाओं की क्रेडिट सुविधाएं, या तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत या इन निदेशों के तहत, स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद एआईएफआई द्वारा 'मानक' के रूप में जारी रखी जा सकती हैं या उन्नत की जा सकती हैं।

73. यदि स्वामित्व में परिवर्तन इन निदेशों के तहत लागू किया जाता है, तो 'मानक' के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(1) एआईएफआई इस संबंध में आवश्यक समुचित सावधानी बरतेगा और स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि अधिग्रहणकर्ता दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के संदर्भ में अयोग्य व्यक्ति नहीं है।

(2) एआईएफआई स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि 'नया प्रवर्तक' मौजूदा प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह के रूप में परिभाषित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में व्यक्ति / संस्था / अनुषंगी / सहयोगी आदि (घरेलू और साथ ही विदेशी) नहीं है।

(3) नए प्रवर्तक ने उधारकर्ता इकाई की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत और साथ ही मताधिकार हासिल कर लिया होगा और उधारकर्ता इकाई का एकल सबसे बड़ा शेयरधारक होगा।

(4) नया प्रवर्तक उधारकर्ता इकाई के 'नियंत्रण' में होगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / किसी अन्य लागू विनियम / लेखांकन मानकों द्वारा जारी विनियमों में 'नियंत्रण' की परिभाषा के अनुसार है।

(5) पैरा 36 के अनुसार समाधान योजना के कार्यान्वयन की शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

74. स्वामित्व में परिवर्तन पर, उधार लेने वाली इकाई के सभी बकाया ऋण / क्रेडिट सुविधाएं निगरानी अवधि के दौरान सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं के संबंध में संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

75. यदि खाता निगरानी अवधि के दौरान किसी भी समय संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो यह एक नई समीक्षा अवधि को ट्रिगर करेगा।

76. उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख को उक्त खाते पर एआईएफआई द्वारा रखे गए प्रावधानों की मात्रा (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) निगरानी अवधि के अंत के बाद ही वापस ली जा सकती है, जो संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है।

77. यदि सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 के तहत अनिवार्य लॉक-इन अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों को एआईएफआई के पास संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया है और लॉक-इन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा चूक के परिणामस्वरूप लॉक-इन अवधि के दौरान गिरवी रखे शेयरों को एआईएफआई को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन शेष लॉक-इन अवधि के लिए शेयर एआईएफआई के पास अवरुद्ध रहेंगे ।

अध्याय VI - पुनर्रचना के विशेष मामले

ए. बिक्री और लीजबैक लेनदेन

78. उधारकर्ता की आस्तियों की बिक्री और पट्टे पर वापस लेनदेन या इसी तरह के अन्य लेनदेन को विक्रेता के अवशिष्ट ऋण के संबंध में एआईएफआई बहियों में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के उद्देश्य से पुनर्रचना की घटना माना जाएगा, साथ ही खरीदार का ऋण माना जाएगा यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

(1) आस्तियों का विक्रेता वित्तीय कठिनाई में है;

(2) महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थात विशिष्ट आस्ति से खरीदार के राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक, विक्रेता से नकदी प्रवाह पर निर्भर है; और

(3) विशिष्ट आस्ति की खरीद के लिए खरीदार द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत या उससे अधिक ऋणदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिनके पास पहले से ही विक्रेता के लिए क्रेडिट एक्सपोजर है।

बी. विदेशी मुद्रा उधार

79. यदि उधार / निर्यात अग्रिम (किसी भी मुद्रा में, जहां भी अनुमति दी गई है) समान / अन्य मुद्रा में नामित ऋणों के पुनर्भुगतान / पुनर्वित्त के उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं:

(1) एक ऋणदाता से जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है (जहां अनुमति है); या

(2) गारंटी / आपाती साख पत्र / चुकौती आश्वासन पत्र आदि के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली से समर्थन (जहां अनुमति हो) के साथ हो तो ,

ऐसी घटनाओं को एआईएफआई द्वारा 'पुनर्रचना' माना जाएगा यदि संबंधित उधारकर्ता वित्तीय कठिनाई से ग्रस्त है।

सी. धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक करने वाले उधारकर्ता

80. जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक की है, साथ ही कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, पुनर्रचना के लिए अयोग्य रहेगा।

81. हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां मौजूदा प्रवर्तकों को उप-पैरा 73 (1) से (4) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले नए प्रवर्तकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उधारकर्ता कंपनी ऐसे पूर्व प्रवर्तकों / प्रबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाती है तो एआईएफआई पूर्व प्रवर्तकों / प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की निरंतरता के लिए पूर्वाग्रह के बिना, उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्रचना पर विचार कर सकता है।

82. इरादतन चूककर्ता या कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बाद पुनर्रचना के लिए पात्र होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन) निदेश, 2025 के संदर्भ में इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपायों के अधीन है।

डी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना

83. समझौता निपटान का उद्देश्य एआईएफआई के सर्वोत्तम हित में, न्यूनतम खर्च पर संकटग्रस्त उधारकर्ता से अधिकतम वसूली करना होगा।

84. समझौता निपटान उधारकर्ताओं के लिए अधिकार के मामले में उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक एआईएफआई द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर प्रयोग किया जाने वाला विवेक है।

85. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना भविष्य की आकस्मिक वसूली या एआईएफआई द्वारा वसूली से संबंधित एआईएफआई और उधारकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों के लिए पूर्वाग्रह के बिना होंगे, इस तरह के दावों के निपटान के समय या बाद में ऐसी प्राप्य की वास्तविक वसूली तक एआईएफआई के तुलन पत्र पर किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं होने के अधीन।

बशर्ते एआईएफआई के तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त ऐसे कोई भी दावे व्यवस्था को पुनर्रचना के रूप में माना जाएगा।

86. पैरा 85 के बावजूद, ऐसा समझौता निपटान जहां तय की गई निपटान राशि के भुगतान की अवधि तीन महीनों से अधिक हो, उन्हें पुनर्रचना माना जाएगा।

87. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान से जुड़ी कोई भी व्यवस्था पुनर्रचना की परिभाषा के अंतर्गत भी आएगी और उस पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

88. तकनीकी बट्टे-खाते डालना, एआईएफआई द्वारा की गई एक लेखा प्रक्रिया है जिसे अशोध्य ऋणों को तुलन पत्र से साफ करने के लिए किया जाता है जो या तो अप्राप्य माने जाते हैं या जिनकी वसूली में उधारदाताओं के असमान संसाधनों की खपत होने की संभावना है। हालाँकि, इस तरह के तकनीकी बट्टे-खाते डालना में उधारकर्ता के विरुद्ध दावों की कोई छूट शामिल नहीं है और इस प्रकार एआईएफआई के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाएगा। तकनीकी बट्टे-खाते डालना से पहले की स्थिति के मुकाबले उधारकर्ताओं का कानूनी दायित्व और उनके लिए इस तरह के चूक की लागत अपरिवर्तित रहती है।

89. आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मामले में, प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण सहित अवशिष्ट एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ मूल एक्सपोजर के संदर्भ में होंगी।

बशर्ते आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि सहित प्रावधानीकरण की राशि आस्ति के सकल मूल्य पर गणना के अनुसार मौजूदा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

90. समझौता निपटान और किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी बट्टे खाते में डालने के संबंध में कम से कम तिमाही आधार पर अगले उच्च प्राधिकारी को सूचना का रिपोर्टिंग तंत्र होगा।

बशर्ते एमडी एवं सीईओ / बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।

91. बोर्ड उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:

(1) समझौता निपटान और / या तकनीकी *बट्टे-खाते डालना* (क्यू-ओ-क्यू और वाई-ओ-वाई) के अधीन खातों और राशियों की संख्या में प्रवृत्ति;

(2) उपरोक्त (1) में से, धोखाधड़ी, रेड-फ्लैग, इरादतन चूक और त्वरित अवसान खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विभाजन;

(3) राशि-वार, स्वीकृति प्राधिकारी-वार, और ऐसे खातों का व्यवसाय खंड / आस्ति-वर्गवार समूहीकरण;

(4) तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा।

92. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, एआईएफआई द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए नए जोखिमों को स्वीकार करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक विराम अवधि होगी।

बशर्ते कृषि ऋण एक्सपोजर के अलावा अन्य एक्सपोजर के संबंध में विराम अवधि 12 महीने की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी, जिसमें एआईएफआई अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में उच्च विराम अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

*बशर्ते*यह भी कि कृषि ऋण एक्सपोजर के लिए विराम अवधि एआईएफआई द्वारा उनकी संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कृषि ऋण से भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में सूचीबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित ऋण का संदर्भ होगा।

93. तकनीकी बट्टे-खाते डालना के अधीन एक्सपोजर के संबंध में अपनाई जाने वाली विराम अवधि एआईएफआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी।

94. एआईएफआई ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह के बिना इरादतन चूककर्ताओं या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे-खाते डालना कर सकता है।

95. भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान) निदेश, 2024 और भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन) निदेश, 2025 के संदर्भ में धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपाय, उन मामलों में लागू रहेंगे जहां कोई एआईएफआई ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान में प्रवेश करता है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पैरा 92 और 93 में निर्दिष्ट विराम अवधि, ऐसे दंडात्मक उपायों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी।

एफएक्यू1: सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए एआईएफआई की अनुमति देने का क्या तर्क है?

प्राथमिक विनियामक उद्देश्य किसी एआईएफआई को बिना किसी देरी के चूक में पैसे की वसूली के लिए विभिन्न मार्गों से सक्षम करना है। समय मूल्य हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप आस्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली को बाधित करती है। समझौता निपटान को इन निदेशों के तहत एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जब धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आती है तो एआईएफआई के लिए अनिवार्यताएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना एआईएफआई के तुलन पत्र पर इस तरह के एक्सपोजर जारी रखने से एआईएफआई की निधि एक अनुत्पादक आस्ति में लॉक हो जाएंगी, जो वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़े नीतिगत मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की लागत अपराधियों द्वारा वहन नहीं की जाती, तब तक सुरक्षा उपायों के अधीन, एआईएफआई द्वारा शीघ्र वसूली एक पसंदीदा विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही या प्रारम्भ की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य के अपराधी कानूनी दंड से बच न सकें।

एफएक्यू 2: एआईएफआई को धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खातों की पुनर्रचना करने की अनुमति नहीं है, सिवाय स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए एक अलग निष्पादन क्यों निर्धारित किया जाता है?

आम तौर पर पुनर्रचना में पुनर्रचना के बाद भी उधारकर्ता इकाई का निरंतर एक्सपोजर रखने वाला एआईएफआई शामिल होता है और इसलिए, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के मामले में, एआईएफआई को उधारकर्ता इकाई के साथ अपने क्रेडिट संबंध को जारी रखने की अनुमति देना नैतिक खतरे से भरा होगा। दूसरी ओर, एक समझौता निपटान में उधारकर्ता के साथ एआईएफआई का पूर्ण अलगाव शामिल होता है। इसलिए, किसी एआईएफआई को अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उधारकर्ताओं के साथ निपटान की अनुमति देने से वसूली की संभावना बढ़ जाएगी।

96. इन निदेशों के तहत उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान, प्रयोज्य किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना होंगे।

97. जहां कहीं भी किसी एआईएफआई ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की है और वहाँ ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।

98. पैरा 83 से 97 में निहित अपेक्षाओं के अलावा, लोक अदालतों के माध्यम से एआईएफआई द्वारा किए गए समझौते के निपटान के मामलों में निम्नलिखित लागू होगा:

(1) सिविल न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों को संदर्भित किए जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये होगी।

(2) किसी एआईएफआई को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के मामलों को हल करने के लिए डीआरटी / डीआरएटी द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भाग लेने की अनुमति है।

ई. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

99. इस पैरा 101 से 119 में निहित निदेश उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जहां 1 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त किया गया है, जिसके लिए 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित परियोजना वित्त पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, जो अन्यथा निरस्त माने जाएंगे, लागू होंगे।

100. पैरा 99 में दिए गए अनुदेशों के बावजूद, 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद ऐसी परियोजनाओं में नई क्रेडिट घटना और / या ऋण अनुबंध में भौतिक नियमों और शर्तों में परिवर्तन का कोई भी समाधान पैरा 101 से 119 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

101. एआईएफआई परियोजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा और किसी भी तनाव के निर्माण की निगरानी करेगा और उससे उम्मीद की जाएगी कि वह समय से पहले समाधान योजना प्रारम्भ करे।

102. निर्माण चरण के दौरान किसी भी ऋणदाता के साथ क्रेडिट घटना का घटित होना, इन निदेशों के अध्याय III के संदर्भ में सामूहिक समाधान को ट्रिगर करेगी।

स्पष्टीकरण: इन निदेशों के अध्याय III में ' चूक' का संदर्भ परियोजना वित्त खातों के प्रयोजन के लिए 'क्रेडिट घटना' के रूप में पढ़ा जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

103. एआईएफआई के साथ ऐसी किसी भी क्रेडिट घटना की रिपोर्ट एआईएफआई द्वारा साप्ताहिक आधार पर सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) को भेजने के साथ ही, पैरा 15 और 16 के अनुपालन में CRILC मुख्य रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी जाएगी।

104. एआईएफआई, जो एक सहायता संघ (कंसोर्टियम) / बहु ऋण व्यवस्था का हिस्सा है, ऐसी क्रेडिट घटना की के घटित होने की रिपोर्ट कंसोर्टियम / बहु ऋण व्यवस्था के अन्य सभी सदस्यों को दी जाएगी।

105. पैरा 103 के अनुसार CRILC रिपोर्टिंग पर अनुदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

106. एआईएफआई समीक्षा अवधि के दौरान उधारकर्ता के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा करेगा।

107. समीक्षा अवधि के दौरान एआईएफआई का आचरण, जिसमें आंतर ऋणदाता करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना और जहां अपेक्षित हो, समाधान योजना को लागू करने का निर्णय, इन निदेशों के अध्याय III द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

108. यदि मूल / विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से जुड़ी समाधान योजना, जैसा भी मामला हो, परियोजना वित्त खाते में लागू की जाती है जिसे मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में परियोजना वित्त की मंजूरी, संवितरण और निगरानी के लिए निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवेकपूर्ण शर्तों को किया जाता है, तो ऐसे खाते का आस्ति वर्गीकरण 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा, बशर्ते परिकल्पित समाधान योजना शुरू से ही निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप हो:

(1) अनुमत डीसीसीओ स्थगन - मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, समान या कम अवधि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में परिणामी बदलाव के साथ (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि सहित), निम्नलिखित समय सीमा के भीतर विस्तारित किया जाता है:

	अवसंरचना परियोजनाएं	**गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)**
मूल डीसीसीओ से डीसीसीओ के स्थगन की अनुमति दी गई	3 साल तक	2 साल तक

स्पष्टीकरण: सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (समय-समय पर अद्यतन) के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।

(2) लागत अतिप्रवाह - एआईएफआई उप पैरा (1) के अनुपालन में अनुमत डीसीसीओ स्थगन से जुड़े लागत अतिप्रवाह को समाधान योजना के भाग के रूप में वित्तपोषित कर सकता है और खाते को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) निर्माण के दौरान ब्याज के अतिरिक्त मूल परियोजना लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की लागत में वृद्धि।

(ii) लागत में वृद्धि को वित्तीय समापन के समय एआईएफआई द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और जिसे सुविधा के अंतर्गत ड्रॉ-डाउन होने तक बिना किसी अबाधित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।

(iii) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, ऐसे मामलों में जहां वित्तीय समापन के समय वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी, या स्वीकृत की गई थी लेकिन बाद में नवीनीकृत नहीं की गई, ऐसे अतिरिक्त निधीयन (फंडिंग) का मूल्य उस प्रीमियम पर होगा जो पूर्व-स्वीकृत वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा पर लागू होगा। एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण-अनुबंधों में वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त एक्सपोजर प्रीमियम को निर्दिष्ट किया जाए, जिसे ऐसी सुविधाओं की स्वीकृति के समय वास्तविक एक्सपोजर मूल्यांकन के आधार पर ऊर्ध्वगामी रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(iv) डी / ई अनुपात, बाहरी क्रेडिट रेटिंग (यदि कोई हो) आदि जैसे वित्तीय मापदंड ऐसे लागत अतिप्रवाह वित्तपोषण के बाद एआईएफआई के पक्ष में अपरिवर्तित रहते हैं या बढ़ जाते हैं।

स्पष्टीकरण: उन परियोजनाओं के लिए जहां सभी उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ से कम है, आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर विचार किया जा सकता है, यदि परियोजना को मूल रूप से बाहरी रूप से क्रेडिट रेट नहीं किया गया था।

(3) दायरा और आकार में परिवर्तन – किसी परियोजना वित्त खाता जहां परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना परिव्यय में वृद्धि के कारण डीसीसीओ विस्तार की आवश्यकता होती है, को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने के अधीन 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) मूल परियोजना के संबंध में किसी भी लागत-अतिवृद्धि को छोड़कर परियोजना लागत में वृद्धि मूल परिव्यय का 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, जैसा भी मामला हो।

उदाहरण I:

परियोजना की मूल लागत - 1,000 करोड़ रुपये

परियोजना की संशोधित लागत - 1,200 करोड़ रुपये

लागत में वृद्धि - 200 करोड़ रुपये अर्थात 20%

लागत में वृद्धि का स्त्रोत

ए. दायरे में परिवर्तन 18%

बी. अतिप्रवाह लागत 2%

दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि केवल 180 करोड़ (18%) है। चूंकि दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 18% है, जो कि 25% से कम है, इसलिए कोई आस्ति वर्गीकरण लाभ नहीं होगा।
उदाहरण II : परियोजना की मूल लागत - 1,000 करोड़ रुपये परियोजना की संशोधित लागत - 1,400 करोड़ रुपये लागत में वृद्धि - 400 करोड़ रुपये अर्थात 40% लागत में वृद्धि का स्त्रोत ए. दायरे में परिवर्तन 30% बी. अतिप्रवाह लागत 10% दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि ₹300 करोड़ (30%) है। चूंकि दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 30% है, जो 25% से अधिक है, इसलिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा।

(ii) एआईएफआई दायरे में वृद्धि को मंजूरी देने और नया डीसीसीओ तय करने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करता है।

(iii) पुन: रेटिंग पर (यदि पहले से ही रेटिंग दी गई है), नई बाहरी क्रेडिट रेटिंग पिछले बाहरी क्रेडिट रेटिंग से एक पायदान से अधिक नीचे नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते, यदि परियोजना ऋण के दायरे या आकार में वृद्धि के समय अनरेट नहीं किया गया था, तो यह उन परियोजनाओं के मामले में दायरे या आकार में ऐसी वृद्धि पर बाहरी रूप से रेटेड निवेश ग्रेड होना चाहिए जहां सभी उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है।

109. 'दायरे में परिवर्तन' के कारण मानक आस्ति वर्गीकरण लाभ परियोजना के जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा।

110. पैरा 108 में निर्दिष्ट सभी मामलों में, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों की समाप्ति से पहले सभी उधारदाताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:

(1) ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन / प्रतिभूति प्रभार / प्रतिभूतियों की पूर्णता सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़, कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप पूरे किए जाते हैं;

(2) नई पूंजी संरचना और / या वित्तपोषण समझौते में परिवर्तन ऋणदाता और उधारकर्ता की बहियों में विधिवत रूप से प्रतिबिंबित होते हैं।

111. यदि डीसीसीओ में परिवर्तन से संबंधित समाधान योजना को पैरा 108 और / 110 के संदर्भ में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता है, तो खाते को तुरंत एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।

112. उप-पैरा 108 के अनुपालन के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किया गया एक परियोजना वित्त खाता, वास्तविक डीसीसीओ के बाद खाते के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद ही अपग्रेड किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण: पैरा 4 (14) में परिभाषित संतोषजनक प्रदर्शन इस मामले में लागू होगा।

113. उप-पैरा 110 के अनुपालन के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किया गया एक परियोजना वित्त खाता, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन पर अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि डीसीसीओ के स्थगन के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त न हो।

114. किसी परियोजना वित्त खाते के संबंध में आय निर्धारण जहां मूल / विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से संबंधित समाधान निम्न प्रकार होगा:

(1) एआईएफआई परियोजना वित्त जोखिमों के संबंध में उपार्जन के आधार पर आय को मान्यता दे सकता है जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) एनपीए के लिए, आय निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान– आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित निदेशों के अनुसार होगा।

115. जिन खातों ने पैरा 108 से 111 के अनुसार डीसीसीओ स्थगन का लाभ उठाया है और उन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एआईएफआई भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट लागू मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त, स्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए अवसंरचना परियोजना ऋणों के

लिए 0.375 प्रतिशत और गैर-अवसंरचना परियोजना ऋणों (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित) के लिए 0.5625 प्रतिशत के अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाएगा।

अवसंरचना परियोजनाएं	**गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)**
उदाहरण III: वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 3.750 करोड़	**उदाहरण IV :** वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 5.625 करोड़
उदाहरण V: वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2027 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 18.750 करोड़ रुपये	**उदाहरण VI:** वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2027 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 28.125 करोड़ रुपये
उदाहरण VII वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2029	***उदाहरण VIII*** वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2028

आस्ति वर्गीकरण - एनपीए निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 150 करोड़	आस्ति वर्गीकरण - एनपीए अनुरक्षित किए जानेवाले विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 150 करोड़ रुपये

116. पैरा 115 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर उलट दिए जाएंगे।

117. पैरा 115 में निर्दिष्ट मौजूदा परियोजनाओं के लिए पैरा 99 में निर्धारित प्रावधान लागू नहीं होंगे और ऐसे परियोजना ऋण 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रावधानीकरण के उद्देश्य से प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होते रहेंगे, जो अन्यथा निरस्त माने जाएंगे।

118. पैरा 117 में दिए गए अनुदेशों के बावजूद, ऐसी परियोजनाओं में नए क्रेडिट घटना के किसी समाधान और / या ऋण अनुबंध में भौतिक नियम और शर्तों में परिवर्तन के मामले में, पैरा 115 में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर लागू होंगे जैसे कि ये 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत किए गए थे।

119. परियोजना ऋणों के लिए प्रावधानीकरण, जिन्हें 'मानक' (निर्माण या परिचालन चरण) या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगा।

अध्याय VII - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन:

120. एआईएफआई, मौजूदा विनियामकीय मानदंडों के अधीन, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर, सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है।

121. योजना का कोई भी प्रावधान जो उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में हो या विवेकपूर्ण कारणों से उसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उसे डीआरएस को डिजाइन करते समय परामर्श चरण के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/ प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाएं।

122. एआईएफआई स्पष्ट रूप से उस बकाया राशि का निर्धारण करेगा जो डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी बहियों में क्रिस्टलीकृत हो सकती है, जिसमें गैर-निष्पादित खातों में संचित ब्याज भी शामिल है, ताकि सरकार वित्तीय भागीदारी की सीमा के लिए उचित रूप से व्यवस्था कर सके।

123. एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाए ताकि तकनीकी आधार पर प्राधिकारियों द्वारा बाद में प्रवेश न किया जा सके।

124. योजना के नियम और शर्तों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पहलू, जिसमें नए क्रेडिट के विस्तार के लिए विराम अवधि, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि शामिल हैं, प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ प्राप्त

करने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त करते समय उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

125. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में एआईएफआई द्वारा योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में या उसके कार्यान्वयन के बाद उपार्जित लेकिन अप्राप्त ब्याज की कोई भी छूट और / या मूलधन का त्याग, एक समझौता निपटान माना जाएगा और पैरा 83 से 98 में निहित विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

126. यदि डीआरएस के हिस्से के रूप में एआईएफआई द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के संपूर्ण बकाया देय राशि को कवर करती है, जिसमें एआईएफआई द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तारीख तक अर्जित मूलधन और ब्याज शामिल है, तो इससे उधारकर्ता के ऋण दायित्वों का समापन हो जाएगा।

127. ऐसे मामलों में जहां योजना के हिस्से के रूप में एआईएफआई द्वारा प्राप्त धन उधारकर्ता के पूरे बकाया देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट एक्सपोजर (मूलधन और / या उपार्जित ब्याज) होता है, अवशिष्ट एक्सपोजर के आस्ति वर्गीकरण का मूल्यांकन मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध के नियम और शर्तों में कोई भी परिवर्तन / आशोधन इन निदेशों में परिभाषित पुनर्रचना के परीक्षण के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

128. ऐसे उधारकर्ताओं को कोई भी नया क्रेडिट एक्सपोजर प्रासंगिक आंतरिक नीति के तहत एआईएफआई के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा, जो मौजूदा लागू नियमों के अधीन होगा।

129. योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों को एआईएफआई की रिपोर्टिंग इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाएगी।

130. डीआरएस के कारण सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्य राशियाँ नहीं बनायी जाएगी और एआईएफआई द्वारा धन प्राप्त होने तक उधारकर्ता पर एक्सपोजर जारी रहेगा।

131. निधि प्राप्त होने तक, एआईएफआई आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना जारी रखेगा और जहां भी खाते गैर-निष्पादित हैं, एआईएफआई ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वसूली उपायों के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

132. पैरा 120 से 131 में निहित निदेश 31 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगे और इन अनुदेशों में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

133. इन अनुदेशों के संदर्भ में, एक मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी राज्य सरकारों (अनुलग्नक) के साथ साझा की गई है, ताकि सरकार, ऋणदाता, उधारकर्ता आदि सहित हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी गैर-संरेखण के परिवर्जन के लिए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सके।

134. 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक समय से सरकार के पास लंबित किसी भी बकाया राशि पर 100 प्रतिशत विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा।

135. एआईएफआई पैरा 134 में उल्लिखित बकाया राशि के निपटान के लिए आवश्यक करेगा और संबंधित सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

अध्याय VIII: पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का विवेकपूर्ण उपचार

ए. पुनर्रचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का आस्ति वर्गीकरण

136. पैरा 136 से 138 उन मामलों पर लागू होगा जहां पुनर्रचना का कोई कार्य उधारकर्ता द्वारा जारी नई प्रतिभूतियों का निर्माण करता है जिसे एआईएफआई, पुनर्रचना से पहले के एक्सपोजर के हिस्से के बदले में रखेगा।

137. निधिक ब्याज मियादी ऋण (एफआईटीएल)/ ऋण / मूलधन / अवैतनिक ब्याज के रूपांतरण द्वारा बनाए गए ऋण / इक्विटी लिखत, जैसा भी मामला हो, एआईएफआई द्वारा उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखे जाएंगे जिसमें पुनर्गठित अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है।

138. एफआईटीएल / ऋण या इक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में आगे की गतिविधि भी पुनर्रचित अग्रिम के बाद के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

बी. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत लिखतों के संबंध में प्रावधान

139. पुनर्रचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहित लिखतों पर लागू प्रावधान निम्नलिखित से अधिक होंगे :

(1) एआईएफआई द्वारा धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में लागू प्रावधान; या

(2) पैरा 140 से 148 में दिए लिखतों के उचित मूल्यांकन के आधार पर लागू प्रावधान।

सी. पुनर्रचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहीत लिखतों का मूल्यांकन

140. मुख्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से उत्पन्न होने वाले लिखतों का मूल्यांकन नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी मूल्यांकन और उधारकर्ताओं के दबावग्रस्त नकदी प्रवाह को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों के आधार पर किया जाएगा।

141. सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे लिखतों के मूल्यांकन से ऐसे लिखतों से जुड़े नुकसान के एक्सपोजर को दर्शाया गया है।

142. ऋण / सदृश -ऋण / इक्विटी लिखत, भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का परिचालन) निदेश, 2025 में निहित सभी निदेशों के अधीन होंगे, जहां तक वे इन निर्देशों के साथ असंगत नहीं हैं:

143. डिबेंचर / बांड का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का परिचालन) निदेश, 2025 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

144. समाधान योजना के हिस्से के रूप में ऋण को शून्य कूपन बॉन्ड (जेडसीबी) / कम कूपन बॉन्ड (एलसीबी) में परिवर्तित करना और ऐसे लिखतों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का संचालन) निदेश, 2025 में निर्धारित किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन है:

(1) जहां उधारकर्ता उपरोक्त निदेशों के तहत आवश्यक ऋण शोधन निधि का निर्माण करने में विफल रहता है, ऐसे उधारकर्ता के जेडसीबी / एलसीबी का सामूहिक रूप से मूल्य ₹1 होगा;

(2) पूर्व-निर्दिष्ट सेवांत मूल्य के बिना लिखतों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन ₹ 1 पर किया जाएगा।

145. इक्विटी लिखत, जहां मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनका मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया हो या अन्यथा, निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए:

(1) बही मूल्य (यदि कोई हो तो 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' पर विचार किए बिना) जिसका निर्धारण कंपनी के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र से किया जाएगा। जिस तिथि को नवीनतम तुलन पत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक रूप से मूल्य ₹1 प्रति कंपनी पर आंका जाएगा।

(2) बट्टागत नकद प्रवाह विधि जहां बट्टागत कारक पुनर्रचना के बाद अवशिष्ट ऋण पर उधारकर्ता को प्रभारित वास्तविक ब्याज दर है, साथ ही एक एक्सपोजर प्रीमियम भी होता है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखा जाता है। एक्सपोजर प्रीमियम तीन प्रतिशत के न्यूनतम स्तर और 14 प्रतिशत के समग्र बट्टागत कारक के

अधीन होगा। इसके अलावा, परियोजना के उपयोगी उपयोगिता काल के 85 प्रतिशत के भीतर होने वाले नकदी प्रवाह (वर्तमान के साथ-साथ तत्काल संभावित (छह महीने से अधिक नहीं) स्तर के परिचालन से उपलब्ध नकदी प्रवाह) की ही गणना की जाएगी।

146. इक्विटी लिखत, जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया है, या अन्यथा, सामूहिक रूप से ₹1 पर मूल्यांकित किया जाएगा।

147. अधिमान शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान- वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का परिचालन) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा, जो निम्नलिखित आशोधनों के अधीन है:

(1) बट्टागत दर, पुनर्रचना के बाद शेष ऋण पर उधारकर्ता से ली जाने वाली भारित औसत वास्तविक ब्याज दर के न्यूनतम स्तर के साथ 1.5 प्रतिशत के मूल्य बढ़ाने (मार्क-अप) पर भी निर्भर होगी।

(2) जहां अधिमान लाभांश / कूपन की बकाया राशि हैं, उपार्जित लाभांश / कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और उपरोक्त निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत से और अधिक छूट दी जानी चाहिए यदि बकाया राशि एक वर्ष के लिए है, 25 प्रतिशत यदि बकाया राशि दो वर्षों के लिए है इत्यादि (अर्थात, दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ)।

148. यदि किसी एआईएफआई ने समाधान योजना के एक भाग के रूप में ऋण के रूपांतरण पर कोट न किए गए लिखत प्राप्त किए हैं और यदि समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं माना जाता है, तो

ऐसे कोट न किए गए लिखतों का कुल मूल्य उस समय ₹1 होगा और जब तक समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं माना जाता है।

डी. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहीत उपकरणों से आय निर्धारण

149. एफआईटीएल / ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय का 'विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)' के रूप में शैलीबद्ध खाते में एक तदनुरूपी क्रेडिट होना चाहिए।

150. एफआईटीएल / ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय को केवल एआईएफआई द्वारा लाभ और हानि खाते में निम्नानुसार मान्यता दी जा सकती है:

(1) एफआईटीएल / ऋण लिखत: केवल बिक्री या मोचन पर, जैसा भी मामला हो;

(2) अप्राप्त इक्विटी / उद्धृत इक्विटी (जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है): केवल बिक्री पर;

(3) उद्धृत इक्विटी (जहां मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है): उन्नयन की तिथि को इक्विटी का बाजार मूल्य, ऐसी इक्विटी में परिवर्तित अप्राप्त आय की राशि से अधिक नहीं। इक्विटी के मूल्य में बाद के परिवर्तनों का भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान– निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

अध्याय IX – वियामकीय छूट

ए. आरबीआई के विनियमों से छूट

151. ऋण के रूपांतरण के माध्यम से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को आरबीआई द्वारा निर्धारित असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंध और विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है।

152. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनर्रचना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजरों, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह एक्सपोजर पर नियामक सीमा / प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

153. पैरा 152 के बावजूद, ऐसे अधिग्रहण के लिए हर महीने आस्ति गुणवत्ता और प्रकटीकरण की नियमित डी.बी.एस. विवरणी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग, केंका को रिपोर्ट किया जाएगा और वार्षिक वित्तीय विवरणों में एआईएफआई द्वारा खातों के नोट्स में प्रकटीकरण की अपेक्षित होगा।

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट

154. सेबी ने कुछ शर्तों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों के अनुसार पुनर्रचना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की है।

155. आईसीडीआर विनियम, 2018 के उप-विनियम 158 (6) (ए) में निहित आवश्यकताओं के संदर्भ में, इक्विटी का निर्गम मूल्य (1) अथवा (2) में से कम होगा:

(1) 'संदर्भ तिथि' से पहले के 26 सप्ताहों के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा (वॉल्यूम) भारित औसत मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत या 'संदर्भ तिथि' से पहले के दो सप्ताहों के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा (वॉल्यूम) भारित औसत कीमतों के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत, जो भी कम हो; और

(2) बही मूल्य: नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र (यदि कोई हो तो 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' पर विचार किए बिना) से प्रति शेयर बही मूल्य की गणना की जानी है, यदि कोई हो तो पहले पुनर्रचना के बाद नकदी प्रवाह और वित्तीय के लिए समायोजित किया जाएगा, यदि कोई हो। जिस तिथि को नवीनतम तुलन पत्र किया जाता है वह पुनर्रचना की तारीख से 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयरों का सामूहिक रूप से मूल्य ₹1 प्रति कंपनी पर आंका जाएगा।

156. ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तिथि होगी जिस पर एआईएफआई पुनर्रचना योजना को मंजूरी देता है। परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तिथि होगी जिस पर एआईएफआई परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को इक्विटी में परिवर्तित करने की मंजूरी देता है।

अध्याय X - विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

157. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण व्यापार व्यवधानों से ऋण के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, एआईएफआई भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 दिनांक 14 नवंबर, 2025 के तहत निर्दिष्ट पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय दे सकते सकते हैं। इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ, उपायों के लिए एक सावधि विधि खंड शामिल किया गया है।

अध्याय XI - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

158. इन निदेशों के जारी होने के साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

159. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त

सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व अर्जित, उपार्जित या उसके तहत अर्जित;

(2) कोई भी दंड , जब्ती, या कोई भी सजा जो उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुई है;

(3) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या जुर्माना के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकती है जैसे कि उन निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं

160. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

161. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के प्रयोज्यता या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक को आवश्यक

प्रतीत होता है, तो वह यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक

मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)

कवरेज और अर्थ

1. मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) के प्रयोजन के लिए, ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिनमें उधारकर्ताओं के लक्षित खंड के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए वित्तीय अधिकारियों द्वारा वित्त पोषण शामिल है जिसे विनियमित संस्थाओं को त्याग / छूट देने की आवश्यकता होती है।

2. ऐसी किसी भी डीआरएस की घोषणा / अधिसूचना में इस प्रकार के समर्थन की घोषणा करने की आवश्यकता वाली विशिष्ट तनाव या संकट की स्थिति शामिल होनी चाहिए। क्रेडिट संस्कृति के लिए इस तरह के डीआरएस के व्यापक निहितार्थ को देखते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में स्पष्ट राजकोषीय समर्थन के माध्यम से व्यापक आधार वाले राहत उपायों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है जब वित्तीय तनाव को कम करने के अन्य उपाय विफल हो गए हों और डीआरएस को केवल अंतिम उपाय के रूप में माना गया हो ।

अधिसूचना-पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए समन्वित कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ जुड़ सकती हैं। इन योजनाओं में उधारकर्ताओं की

पहचान, प्रभाव का आकलन, कार्यान्वयन समय-सीमा, उधारदाताओं को सरकार द्वारा देय राशि के निपटान से संबंधित मुद्दों का समाधान आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

4. डिजाइन विशेषताओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीआरएस क्षेत्र / राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करे या उधारकर्ता सेगमेंट में नैतिक संकट उत्पन्न न हो। क्रेडिट निपटान पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना का वित्तपोषण

5. आवश्यक निपटान राशि को पूरी तरह से कवर करने के लिए किसी भी प्रस्तावित डीआरएस के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान / निधियन अग्रिम रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहां विनियमित संस्थाओं की सरकार के पास बकाया राशि है जो कि पहले की डीआरएस योजनाओं से संबंधित है तो नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णता: पूर्व-वित्त पोषित आधार पर की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस केवल प्रभावित उधारकर्ताओं पर लक्षित होना चाहिए और इसमें समय पर पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंधात्मक वचन-पत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इसमें वस्तुनिष्ठ आधार पर पात्र उधारकर्ताओं का निर्धारण करने के लिए मानदंड, सरकार की ओर से धन के निपटान में देरी के क्षतिपूर्ति खंडों के साथ-साथ दावा दाखिल करने / जमा करने की कट-ऑफ तिथियों सहित गंभीर/महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समय-सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

7. डीआरएस को सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं से धन प्राप्त करने की तारीख तक मूलधन और संचित ब्याज सहित कवर किए जा रहे उधारकर्ताओं की पूरी बकाया राशि शामिल करना चाहिए ।

8. डीआरएस को विनियमित इकाई की बहियों में सरकार से प्राप्य राशि के सृजन आवश्यकता नहीं **है** । विनियमित संस्थाओं का उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर जारी रहेगा और सरकार से प्राप्त निधि की सीमा तक कम हो जाएगा।

9. योजना का संपूर्ण कार्यान्वयन और विनियमित संस्थाओं के प्रति सरकारों द्वारा दावों का निपटान आम तौर पर 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

10. डीआरएस में रिज़र्व बैंक **/** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किसी भी विनियामक निदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

11. डीआरएस के डिजाइन में कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व डालता है जिसमें सम्मिलित है :

ए. उधारकर्ता से अपने देय राशि की/का आंशिक या संपूर्ण छूट / त्याग;

बी. उन उधारकर्ताओं को नया ऋण प्रदान करें जिनका ऋण माफ 1कर दिया गया है;

सी. भविष्य में बजटीय समर्थन की प्रत्याशा में कोई प्रतिबद्धता न करें;

डी. उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए, सरकार से धन की प्राप्ति लंबित होने पर, उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का अनुसरण करना बंद करें।

तथापि, यदि विनियमित संस्थाएं डीआरएस के डिजाइन के दौरान या उसके बाद में, अपने बोर्ड की अनुमोदित नीतियों के अनुसार उपरोक्त में से किसी पर सहमत होती हैं, तो वह लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगा।